setting up refineries are examined based on techno-economic consideration and demand/supply scenario. LOIs have been issued to five private sector refineries for domestic tarrif area and seven under private sector for EOU.

गरीबों के उत्थान के लिये बजटीय प्रावधान

2198. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उत्थान के लिये न तो कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और न ही कोई बजटीय प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कोई कार्यक्रम कब तक तैयार किया जाएगा और गुजरात सहित सभी राज्यों को धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के अलघ): (क) से (ग) जी, नहीं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख गरीबी उन्मूलन स्कीमें यह हैं:(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), (2) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), एवं (3) रोजगार आश्वासन स्कीम। प्रमुख शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यह हैं, (1) नेहरू रोजगार योजना (2) गरीबों के लिए शहरी प्राथमिक सेवाएं एवं (3) प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई यू पी ई पी)। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों हेतु बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इनसे प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को निधियां आवंटित की गई जिसमें गुजरात राज्य भी शामिल है।

Digging of Tubewells in Eastern States

2199. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have made any review of the progress of work pertaining to digging energisation tubewells and pump-sets in Orissa and other eastern States; and

(b) if so, the details of funds allocated by Government for the above work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VARMA): (a) The review of work relating to energisation of tube-wells and pumpsets in done by the State Govenrments. Since 1.10.1996 tube-wells have been permitted under Million Wells Scheme (MWS), it will be too early to review the progress of this work.

(b) State-wise details of funds allocated (central) during the current year to eastern States under MWS for dug wells and the financial assistance proposed to be provided through Rural Electrification Corporation (REC) for rural electrification works which include village electrification, load intensification in already electrified villages, pumpset energisation, system improvement etc. are as under:-

S. No.	State	Funds allocated under MWS	Funds proposed to be provided to State Electricity Boards through R.E.C.
1.	Bihar	6813.55	1896.00
2.	Orissa	2817.99	1949.00
3.	West Bengal	3112.95	2340.00